



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श०)

(सं० पटना 854) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2016

सं० 22 नि० सि० (औ०)-17-04/2004/2190—श्री कृष्ण चन्द्र कुंवर (आई० डी०-2094), तत्कालीन सहायक अभियन्ता, दादर के विरुद्ध पूर्वी सोन उच्चस्तरीय मुख्य नहर के वि० दू०-136.0 से 209.0 के बीच पुनर्स्थापन कार्य में बरती गई अनियमितता के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 546 दिनांक 15.07.08 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई:—

1. पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर के वि० दू०-136 से 145 के बीच सम्पन्न पुनर्स्थापन कार्य के भुगतान के समय 1/2 कि० मी० की दूरी से ढुलाई कर लाए गए मिट्टी का वास्तविक मापी नहीं किया गया बल्कि प्राक्कलन के अनुसार कुल मिट्टी का 80 प्रतिशत मिट्टी 1/2 कि० मी० दूरी से ढुलाई की दर से भुगतान करने का प्रस्ताव दिया गया जिसके लिए आप दोषी पाए गए।

2. उक्त कार्य में मिट्टी के लिए 1/2 कि० मी० की दूरी से ढुलाई करने के मद में पाँच चालू विपत्र में कुल 100180.53 घन मीटर मिट्टी कार्य का भुगतान किया गया जबकि जॉच दल ने जॉच के क्रम में इस कार्य मद में 48805 घन मीटर मिट्टी का आकलन किया। अतः 51375.53 घन मीटर मिट्टी की मात्रा का भुगतान अधिक किया गया। अन्तिम दो चालू विपत्र का भुगतान आपके द्वारा किया गया है। अतएव अतिरिक्त भुगतेय 51574.53 घन मीटर मिट्टी की मात्रा में से आपके स्तर से 6801.53 घन मीटर अधिक मिट्टी का भुगतान किया गया जिसकी राशि 296590 रूपए थी। अतः इस अतिरिक्त राशि भुगतान के लिए आप दोषी पाए गए।

3. उक्त कार्य से सम्बद्ध बौरो एरिया के पोस्ट लेवल की जॉच आपके द्वारा निश्चित प्रमण्डलों से नहीं कराया गया जिसके लिए आप दोषी पाए गए।

4. उक्त कार्य से संबंधित लेबल बुक में दर्शाए गए बौरो पिट एवं स्थल पर उपलब्ध बौरो पिट की समरूपता जॉच दल द्वारा नहीं पाया गया जिसके लिए आप दोषी पाए गए।

5. उक्त कार्य की समप्ति दिनांक 29.03.04 को हो चुकी थी परन्तु जॉच कार्य के समय तक अन्तिम मापी अंकित नहीं कराया गया था जिसके लिए आप दोषी माने जाते हैं।

श्री कुंवर के दिनांक 31.08.10 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश स०-57 सह पठित ज्ञापांक 501 दिनांक 23.02.15 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) में सम्परिवर्तित किया गया।

आरोपित पदाधिकारी श्री कुंवर द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने बचाव बयान में आरोपवार मुख्यतः निम्न तथ्य दिया गया:-

1. आरोप सं०-1 के संबंध में श्री कुंवर द्वारा बताया गया कि उक्त मिट्टी का कार्य उनके प्रभार ग्रहण दिनांक 24.03.04 के पूर्व ही हो चुका था। दिनांक 25.03.04 को चतुर्थ चालू विपत्र वि० दू० 142.04 से 145.00 दायाँ भाग में कराए गए मिट्टी कार्य का विस्तृत मापी पोस्ट लेवल के अनुसार किया जो 8501.84 घनमीटर था। चारों पिटों से मिट्टी की मात्रा 105130 घनमीटर था जिसमें 93379.02 घनमीटर $1/2$ कि० मी० की दूरी ढुलाई कर लाई गई मिट्टी का भुगतान पूर्व में हो चुका था। चतुर्थ चालू विपत्र में मापी में $1/2$ कि० मी० से ढुलाई की मिट्टी की मात्रा $(105130-93379.02)=11750.98$ घनमीटर पाया गया किन्तु रूपांकन के अनुसार 8501.84 घन मीटर मिट्टी की ही अनुशंसा की गई। स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार 8501.84 घनमीटर का 80 प्रतिशत की दर से यानि 6801.47 घन मीटर मिट्टी के भुगतान का प्रस्ताव दिया था उड़नदस्ता जॉच दल ने स्थल निरीक्षण के क्रम में कार्य संतोषजनक पाया है तथा जॉच दल द्वारा ली गई मापी लगभग सही पाया गया है।

आरोप सं०-2 के संबंध में आरोपित पदाधिकारी का कथन है कि जॉच दल ने इस कार्य मद में 48805 घन मीटर मिट्टी का गलत आकलन किया है। बौरो एरिया के पिटों से ढुलाई की गई मिट्टी की कटाई की गहराई की मापी पिटों के प्री-लेवल एवं पोस्ट लेवल लेकर करने का निदेश स्वीकृत बौरो एरिया आलेख्य में स्पष्ट रूप से मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, डिहरी द्वारा दिया गया है। जॉच प्रतिवेदन में जॉच दल ने समान गहराई वाले बौरो पिट की मापी को यथा संभव मिलाकर गणना की है किन्तु समान पिटों की कुल संख्या से गुणा करना भूल गए हैं जिससे गणना के परिणाम में त्रुटि हुई। कार्य की अंकित मापी एवं जॉचदल द्वारा ली गई मापी का मिलान करने पर जॉच दल द्वारा सही पाया गया है। अतः स्पष्ट है कि मिट्टी की मात्रा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार सही है।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा आरोप सं०-3 के संबंध में कथन है कि बौरो एरिया के पोस्ट लेवल की जॉच सम्बद्ध प्रमण्डल, पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद से कराया गया था जो मुख्य अभियन्ता के आदेश के अनुरूप था।

आरोप सं०-4 के बचाव बयान में आरोपित पदाधिकारी श्री कुंवर का कथन है कि पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर के वि० दू० 136.89 से वि० दू० 145.00 के बीच मिट्टी का कार्य दिनांक 04.03.04 के पूर्व प्रारम्भ हुआ था। मिट्टी का सम्पूर्ण कार्य दिनांक 25.03.04 के पूर्व ही पूर्ण हो चुका था। जॉच दिनांक 10.06.04 को स्थल पर किया गया अर्थात् कार्य समाप्ति के 78 दिनों के बाद स्थल की जॉच हुई। खरीफ मौसम जो हर साल 15 जून से शुरू हो जाता है, के पूर्व किसान अपने खेतों को खेती योग्य तैयार करते हैं। पिटों से मिट्टी की खुदाई मार्च 2004 में राजस्थानी ट्रैक्टर से 800' X 318', 180' X 134' एवं 850' X 400' के आकार में की गई जिसे किसानों द्वारा मेड़ बनाकर छोटे-छोटे खेती योग्य प्लॉट तैयार किए गए जिसके कारण मार्च 2004 के बाद पिटों का स्वरूप जून 2004 तक बदल चुका था। अतः पिटों का स्वरूप बदलने के लिए उन्हें दोषी करार देना सही नहीं है।

आरोप सं०-5 के संबंध में आरोपित का कथन है कि मुख्य नहर के वि० दू० 136.89 से वि० दू० 145 के बीच 20' से 25' गहराई में मिट्टी भराई का कार्य हुआ है। नहर के बाँध में अत्यधिक गहराई में मिट्टी भराई के कारण तकनीकी दृष्टि से एक बरसात के बाद अन्तिम मापी लेकर संवेदक को भुगतान करना उचित होता है। एक बरसात के बाद मिट्टी अधिक बैठ जाती है जिससे संवेदक को अधिक भुगतान नहीं हो पता है। इस संबंध में जॉच आयुक्त की सुनवाई के क्रम में मिट्टी के Specification में मिट्टी के अन्तिम भुगतान से संबंधित Specification की अभिप्रमाणित प्रति समर्पित किया गया था जिसके अनुसार मिट्टी का अन्तिम भुगतान एक बरसात के बाद करना है। एक बरसात के बाद ही मिट्टी कार्य का विपत्र तैयार किया जाता है जिसकी जानकारी संवेदक को भी थी जिसके कारण संवेदक द्वारा विपत्र तैयार करने का कोई भी अनुरोध या दबाव नहीं दिया गया था।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में आरोप सं०-1, 3 एवं 5 को अप्रमाणित तथा आरोप सं० 2 एवं 4 को पूर्ण रूपेण प्रमाणित नहीं पाया गया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि मिट्टी ढुलाई की मात्रा की मापी किए बिना प्राक्कलन के प्रावधान के अनुसार मापी दर्ज कर भुगतान किया गया। उड़नदस्ता जॉच दल द्वारा मात्र 46805 घनमीटर मिट्टी की कटाई का बौरोपिट पाया गया जबकि 100180.53 घनमीटर मिट्टी कार्य का भुगतान कर दिया गया अर्थात् मिट्टी कार्य और कैरेज को जोड़कर 22,40,316 (बाईस लाख चालीस हजार तीन सौ सोलह) रूपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा इस तर्क के साथ इन आरोपों के अप्रमाणित पाया गया कि जब नहर का सेक्शन रूपांकित सेक्शन के अनुरूप है तब मिट्टी के कार्य में 51 प्रतिशत की कमी नहीं माना जा सकता परन्तु अतिरिक्त भुगतान की आशंका व्यक्त की गई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उड़नदस्ता द्वारा दिनांक 12.06.14 से 13.06.14 तक जॉच की गई थी और यह कार्य 29.03.04 को समाप्त हुआ था। साथ ही जॉच कार्यकारी मौसम के अधीन था और वर्षा भी नहीं हुई थी एवं श्री कुंवर उस समय उसी प्रमण्डल में पदस्थापित थे और उनके समक्ष ही जॉच की गई थी। लेवल बुक में अंकित बौरो पिट एवं उड़नदस्ता द्वारा जॉचित बौरो पिट के जॉच फल से स्पष्ट होता है कि न तो बौरो पिट का आकार मिलता है और नहीं बौरो पिट की गहराई मिलती है। स्पष्ट है कि नहर के प्री-लेवल को मैन्यूपुलेट किया गया और कम मिट्टी काटकर अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया। यदि मिट्टी लाई गई होती तो बौरो पिट अवश्य उपलब्ध होता।

असहमति के उक्त बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 517 दिनांक 25.02.15 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) के तहत श्री कुंवर से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में श्री कुंवर द्वारा मुख्य रूप से बताया गया कि उनके प्रभार ग्रहण दिनांक 24.03.04 के पूर्व मिट्टी कार्य पूर्ण था। पिट का पोस्ट लेवल लेकर मिट्टी की गणना की गई। चूंकि मुख्य अभियन्ता का प्री एवं पोस्ट लेवल के आधार पर मिट्टी गणना का निदेश था। प्री लेवल उनके द्वारा नहीं लिया गया और न कभी भी मैन्यूप्लूट किया गया। इसके साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि प्री लेवल बुक उनके द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।

श्री कुंवर से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है। पूर्व के बचाव बयान में कहा गया है कि कार्य समाप्ति के 2-3 महीने बाद जाँच की तिथि के पूर्व किसानों द्वारा बौरोपिट का समतलीकरण कर दिया गया। यह स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि बौरो पिट के गड्ढे का अल्पावधि में समतल किया जाना संभव नहीं है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मिट्टी कटाई हेतु आरोपित पदाधिकारी द्वारा 621112 वर्गफीट एवं जाँच दल द्वारा जाँचित रकबा 719934 है। आरोपित पदाधिकारी का यह भी कहना है कि कराए गए कार्य का पोस्ट लेवल जाँच में सही पाया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि मुख्य अभियन्ता द्वारा प्री लेवल की जाँच कार्य प्रमण्डल, औरंगाबाद से कराने का संशोधित आदेश निर्गत किया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा 5'-0" से 7'-6" तक गहराई अंकित की गई है जबकि जाँच में 2' से 4'-0" गहराई पाया गया है। साधारण मापी से भी उक्त अन्तर की संभावना नहीं है। अतः सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कृष्णचन्द्र कुंवर के विरुद्ध आरोप सं०-1, 2 एवं 4 प्रमाणित है।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री कृष्ण चन्द्र कुंवर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, दादर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध "20 (बीस) प्रतिशत पेंशन पर 5 (पाँच) वर्षों तक रोक" का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है।

सरकार द्वारा निर्णीत दण्ड पर पत्रांक 1867 दिनांक 21.09.16 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

अतः सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री कृष्ण चन्द्र कुंवर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, दादर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए संसूचित किया जाता है।

"20 (बीस) प्रतिशत पेंशन पर 5 (पाँच) वर्षों तक रोक"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 854-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>